शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research

मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly

Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

समावेशी विकास एवं क्षेत्रीय विषमता: भारतीय सन्दर्भ

डॉ॰ अजीत कुमार तिवारी

एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

www.shodh.net

Web Portal of Humanity & Social Science Research

समावेशी विकास एवं क्षेत्रीय विषमता: भारतीय सन्दर्भ

- डॉ॰ अजीत कुमार तिवारी

विगत छः दशकों में भारत ने विकास की प्रक्रिया को काफी गति दी है। विकास के लक्ष्य के लिए हम निरंतर गतिशील हैं। किंतु विभिन्न राज्यों के विकास के आंकड़ों का विश्लेषण यह सिद्ध करता ह कि समावेशी विकास एवं क्षेत्रीय विषमता भारतीय विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है।

विषय संकेत:- समावेशी विकास, क्षेत्रीय विषमता, जनसहभागिता

समानता के साथ विकास (Growth with Equity) हमारी पंचवर्षीय योजनाओं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के नीति निर्धारकों का मुख्य लक्ष्य रहा है लेकिन योजनाओं के उत्तरोत्तर प्रगति के साथ ऐसा प्रतीत होने लगा है कि नेहरू एवं महालनबिस के आर्थिक मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजनाएँ विकास दर के प्रति सचेत तो हैं लेकिन इनका रिसाव प्रभाव इतना प्रभावी नहीं था कि गरीबी, बेरोजगारी एवं आर्थिक विषमता पर कोई सीधा प्रहार कर सके। फलस्वरूप पांचवी पंचवर्षीय योजना में त्तकालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने ''गरीबी हटाओ'' का नारा दिया तथा गरीबी एवं बेरोजगारी पर सीधे प्रहार करने वाली योजनाओं को लागू किया ताकि विकास को अधिक गरीबोन्मुखी (Pro Poor) बनाया जा सके। 80 के दशक तक आते-आते नेहरू के समाजवादी समाज की संकल्पना एवं सार्वजनिक क्षेत्रों पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था की खामियाँ स्पष्ट होने लगी जो कहीं से भी न तो विकासोन्मुखी थी और न ही गरीबोन्मुखी। इन तमाम आर्थिक विकृतियों के समाधान का पथ प्रदर्शक उदारीकरण, निजीकरण एवं सार्वभौमिकीकरण को माना जाने लगा। फलस्वरूप 1990 के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी संरचनात्मक परिवर्तन हुए। तृतीयक क्षेत्र जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मुख्य संघटक है, ने ही मुख्यत: भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक संवृद्धि को 8 से 9% तक पहुंचाया। लेकिन यह भी सत्य है कि आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के 20 वर्षों के तथ्यों का विश्लेषण यह साबित करता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर आर्थिक संवृद्धि के साथ अन्तरवैयक्तिक तथा अन्तरक्षेत्रीय विषमताएँ बढ़ती चली गयी अर्थात आर्थिक सुधारों का मानवीय पक्ष (Human Face) कमजोर हुआ, वितरण के यन्त्रों को हम प्रभावी नहीं बना सके फलस्वरूप ''भारत'' अर्थात कृषि पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ''इण्डिया'' अर्थात उच्च तकनीक पर आधारित शहरी अर्थव्यवस्था के बीच अन्तर बढ़ता चला गया जा सम्भवत: समावेशी विकास की सबसे बड़ी चुनौती है।

यह शोधपत्र भारत में क्षेत्रीय विषमता के विभिन्न आयामों जैसे क्षेत्रीय विषमता की स्थिति, प्रवृति, कारण एवं उसके समाधान हेतु सुझाव पर प्रकाश डालने का प्रयास करेगा जिससे विकास में जनसहभागिता को बढ़ाया जा सके, देश के पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति को तीव्र किया जा सके ताकि एक तरफ महानगरों के असहनीय दबाव कम हो सके वहीं दूसरी ओर युवाओं के पलायन को कम करके गाँव एवं कस्बों को पुन: खुशहाल किया जा सके। इस लेख में राज्यों को अध्ययन का आधार बनाया गया है तथा कुछ मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांकों के माध्यम से क्षेत्रीय विषमता की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का मूल्यांकन-

स्वतंत्रता के पश्चात् इस देश ने विकास के कई स्तर पार किये, अविकसित एवं स्थिर अर्थव्यवस्था के दुश्चक्र को तोड़ते हुए आज यह देश विकासशील देशों की अगली कतार में खड़ा है तथा चीन के पश्चात सर्वाधिक संवृद्धि पद भारत का ही है। संलग्नक 1 से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की एक झलक देखी जा

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly
Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

सकती है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 1990-91 के पश्चात लगभग सभी सूचकांकों में तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है अर्थात भारत में आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के पश्चात विकास की गति तीव्र हुई है।

विकास का एक सैद्धान्तिक पक्ष यह भी है कि विकास के साथ प्राथमिक स्रोत का राष्ट्रीय आय में भाग कम होता जाता है तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का भाग बढ़ता जाता है। इस दृष्टिकोण से भी भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका - 1

सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार वितरण (1993-94 की कीमत पर)

प्रतिशत वितरण (Percentage Distribution)

क्र.सं.	क्षेत्र	1950-51	1980-81	2004-05
1.	प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)	57.8	39.7	20.5
2.	द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)	24.7	23.7	26.3
3.	तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)	28.0	36.6	53.2

स्रोत:- इ.पी.डब्ल्यू.रिसर्च फाउण्डेशन (2002) नेशनल एकाउन्ट्स स्टैटिस्टिक्स फॉर इन्डिया (1950-51 से 2000-01) एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहाँ 1950-51 में प्राथमिक क्षेत्र का भाग 57.8% वहीं 2004-05 में घटकर 20.5% रह गया। द्वितीयक क्षेत्र पूरे योजनाकाल में लगभग स्थिर बना रहा जबकि तृतीयक क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, का भाग 28% से बढ़कर 53.2% हो गया। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के नवीनतम आंकड़े के अनुसार वर्ष 2008-09 में समृद्ध घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का भाग 17%, उद्योगों का भाग 19% एवं सेवा क्षेत्र का भाग 64.5% था। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन सीधा कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर हो गया अर्थात भारतीय उद्योग अर्थव्यवस्था के विकास के संवाहक नहीं बन सके। विचारणीय तथ्य यह है कि द्वितीयक क्षेत्र का स्थिर बने रहना तथा सेवा क्षेत्र के विस्तार में संवृद्धि दर तो 8% स 9% तक कर दी परन्तु इस विकास ने बिना रोजगार के विकास (Jobless Growth) एवं क्षेत्रीय एवं वैयक्तिक रूप से असमान विकास (Inequitable Growth) को जन्म दिया। जो समावेशी विकास की अवधारणा के सर्वथा विपरीत है। शंकर आचार्य[1] ने अपने शोध में भी इस तथ्य को स्पष्ट किया है। सतत् एवं समावेशी विकास के लिए भारतीय विकास की दिशा श्रम आधारित एवं उद्योग जनित विकास (Labour based & industry led growth) द्वारा निर्धारित होनी चाहिए जिसमें कृषि एवं उद्योग का अनुबन्धन (Agriculture-Industry Linkage) अधिक होना चाहिए।

विकास के इस क्रम में गरीबी पर भी कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है। योजना आयोग द्वारा घोषित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत निम्न तालिका से देखा जा सकता है जो सत्त् रूप से घटता हुआ प्रदर्शित है।

www.shodh.net
Web Portal of Humanity & Social Science Research

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly
Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

www.shodh.net
Web Portal of Humanity & Social Science Research

तालिका - 2

वर्ष	1997-98	1983	1993-94	1999-2000
गरीबी का प्रतिशत	51.3	44.5	36.00	26.10

स्रोत :- रीजनल डिसपैरिटिज इन इन्डिया : एन.जे.कूरियन

हाँलाकि योजना आयोग का नवीनतम आंकड़ा विवादास्पद है। गरीबी पर गठित तेन्दुलकर समिति ने वर्ष 2004-05 के लिए 37.2% लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जबकि अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता वाली असंगठित क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोग (NSEUS) ने माना कि देश के 77% लोगों का उपभोग व्यय 20 रूपया प्रतिदिन से कम है। लेकिन इन तमाम अपवादों के पश्चात भी यह स्पष्ट है कि योजनागत विकास का स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव इस देश की गरीबी पर पड़ा है तथा गरीबी कम हुई है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 60 वर्षों के विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप इस देश ने काफी सन्तोषजनक प्रगति की है, अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक स्वरूप भी बदला है तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी हुई लेकिन इस विकास का प्रभावी वितरण हमारी सरकारें नहीं कर सकीं, फलस्वरूप क्षेत्रीय विषमता बढ़ी। योजना आयोग द्वारा की गयी गणना के अनुसार प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का गिनी गुणांक वर्ष 1973 से 2004 के बीच बढ़ा है विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। इस सन्दर्भ में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया[2] ने अन्तर राज्य विषमता (Inter State Inequality) की गणना गिनी गुणंक (Gini Coefficient) के माध्यम से 1980-81 से 1998-99 तक के लिए किया। इस अध्ययन में उन्होने सिद्ध किया कि 80 से 90 के दशक में राज्यों के बीच क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है। 1980-81 में गिनी गुणांक 0.152 था जो 1989-90 में 0.175 तथा 1997-98 में बढ़कर 0.225 हो गया। गिनी गुणांक की नवीनतम गणना के अनुसार वर्ष 2007-08 तक यह बढ़कर 0.245 हो गया जबकि वर्ष 2009-10 में यह घटकर 0.150 हो गया है, अर्थात इधर के कुछ वर्षों में राज्यों के बीच आर्थिक विषमता कम हुई है। कम विकसित राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, इत्यादि ने आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है।

भारत में क्षेत्रीय विषमता:-

भारत में क्षेत्रीय विषमता का विश्लेषण करने के लिए राज्यों को आधार बनाया गया है। कुछ मुख्य सूचकांकों के आधार पर विकास के साथ क्षेत्रीय विषमता की स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। विश्लेषण में 15 मुख्य राज्यों को लिया जा रहा है जो भारतीय जनसंख्या के लगभग 95% है। जिन राज्यों का प्रति व्यक्ति आय (वर्तमान कीमत पर) राष्ट्रीय औसत से अधिक है उसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा गया है तथा जो राज्य राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं उन्हें पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। संलग्नक 2 में विकसित एवं पिछड़े राज्यों के बीच विषमता की स्थिति को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है जो विकसित राज्यों के बीच आर्थिक विषमता की स्थिति को स्पष्ट करता है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक मापदण्ड का एक सूचकांक है जिसमें विकसित राज्यों का औसत (वर्तमान कीमत पर) 50337 है वहीं पिछड़े राज्यों का औसत 24400 है अर्थात प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से विकसित एवं पिछड़े राज्यों में दोगुने का अन्तर है। वर्ष 2008-09 में वर्तमान कीमत पर हरियाणा का निवल प्रति व्यक्ति आय 68914 है जबकि बिहार का निवल प्रति व्यक्ति आय 13663 है अर्थात हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बिहार से 5 गुने से अधिक है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या में भी विकसित एवं पिछड़े राज्यों में महत्त्वपूर्ण अन्तर है। वर्ष 2004-2005 के आंकड़ों के आधार पर विकसित राज्यों के 28.35% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं जबकि पिछड़े राज्यों में 37.17% लोग थे। जहाँ तक कुछ विशिष्ट राज्यों का प्रश्न है केरल में सबसे कम लोग (19.7%) गरीबी रेखा से नीचे हैं जबकि बिहार एवं उड़ीसा में गरीबों की संख्या क्रमश: 54.4% एवं 57.2% थी।

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly

Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

समावेशी विकास एवं क्षेत्रीय विषमता: भारतीय सन्दर्भ

डॉ॰ अजीत कुमार तिवारी

एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

www.shodh.net

Web Portal of Humanity & Social Science Research

खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भी क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलती है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि विकसित राज्यों में जहां पंजाब एवं हरियाणा का प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन क्रमशः 985.1 एवं 562.3 कि. ग्रा. है वहीं केरल में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन मात्र 20.2 कि॰ग्रा॰ है। विकसित राज्यों का औसत 276.4 कि.ग्रा. है जबकि पिछड़े राज्यों का औसत 195.52 कि.ग्रा. हैं। उ॰प्र॰ एवं बिहार की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर ही आधारित है, की प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन का औसत वर्ष 2004-05 में क्रमशः 206.4 कि.ग्रा. एवं 262.9 कि.ग्रा. था। कृषि विकास की सारी सम्भावनाओं के मौजूद रहने के बाद भी उ॰प्र॰ एवं बिहार, पंजाब एवं हरियाणा की तुलना में काफी पीछे है।

प्रति व्यक्ति सकल औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से विकसित राज्यों का औसत 25778.62 है, जबकि पिछड़े राज्यों का औसत मात्र 6362.28 तथा राष्ट्रीय औसत 15337 है। इस दृष्टिकोण से गुजरात सर्वाधिक विकसित राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति सकल औद्योगिक उत्पादन 48468 है जबकि 1378 के साथ बिहार देश का सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है। वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या में मुख्य कामगारों के प्रतिशत के रूप में भी विकसित राज्यों का आँकड़ा 33.77 है वहीं पिछड़े राज्यों को औसत 27.6 है। नगरीय जनसंख्या जो विकास का एक मुख्य सूचक है, तथा अन्तर्राज्यीय प्रवसन की स्थिति को दिखाता है, में भी पिछड़े राज्यों की स्थिति विकसित राज्यों की तुलना में अत्यन्त दयनीय है। जहां एक तरफ वर्ष 2001 में नगरीय जनसंख्या का अनुपात महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु का क्रमशः 42.4% एवं 44% है, वही असम एवं बिहार में क्रमशः 12.9% एवं 10. 5% मात्र है। विकसित राज्यों के नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य घटक पिछड़े राज्यों से जीविका की तलाश में जनसंख्या का प्रवसन है।

आर्थिक विकास में विद्युत की भूमिका सर्वविदित है तथा अर्थव्यवस्था के विकास के साथ इसकी मांग बढ़ती जाती है। प्रति व्यक्ति घरेलू बिजली उपभोग की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत वर्ष 2006-07 में 98.5 किलोवाट घण्टा है, विकसित राज्यों का औसत 146.91 किलोवाट घण्टा है, जबकि पिछड़े राज्यों में यह औसत मात्र 53. 27 किलोवाट घण्टा है। जहां तक कुछ विशिष्ट राज्यों का प्रश्न है पंजाब का प्रति व्यक्ति घरेलू बिजली उपभोग 216.5 किलोवाट घण्टा था वहीं बिहार में यह मात्र 13.9 किलोवाट घण्टा है। साख-जमा अनुपात में भी राज्यों के बीच एक भारी अन्तराल दिखता है। वर्ष 2008 में महाराष्ट्र का साख-जमा 94.7 है वहीं बिहार में यह मात्र 29.7 है। सारणी के अन्तिम कॉलम में सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना का सूचकांक प्रदर्शित किया गया है। हालांकि यह आंकड़ा वर्ष 1999 का है तथा इस बीच राज्यों की स्थिति में बदलाव हुआ है लेकिन राज्यों की प्रवृति का अनुमान इस सारणी से लगाया जा सकता है। पंजाब (187.6) एवं तमिलनाडू (178.7) एवं हरियाणा (137) सामाजिक एवं आर्थिक अधाररभूत संरचना में सबसे उपर है जब कि मध्यप्रदश (76.8) एवं राजस्थान (77.7) एवं बिहार (81.3) इस श्रेणी में सबसे नीचे हं।

उपरोक्त विश्लेषण इस परिकल्पना को साबित करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विकास के सभी चरों में वृद्धि हुयी है लेकिन साथ ही क्षेत्रीय विषमताओं में भी वृद्धि हुयी है अर्थात विकास को समावेशी बनाने में हमारी योजनाएं अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं रहीं।

क्षेत्रीय विषमता पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव-

निम्न तालिका में आर्थिक सुधारों के पहले एवं बाद के दशक में राज्यों के निवल घरेलू उत्पादों एवं प्रति व्यक्ति आय के संवृद्धि दरों की तुलना द्वारा क्षेत्रीय विषमता की प्रवृति एवं उस पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका- 3

	NSDP में संवृद्धि (%)			प्रति व्यक्ति NSDP में संवृद्धि (%)		
राज्य	1980-1981 से 1989-1990	1990-91 से 1999-2000	2000-2001 से 2009-2010	*1980-81 से 1989-19990*	*1990-91 से 1999-2000*	*2000-01 से 2009-2010*

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly

Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

समावेशी विकास एवं क्षेत्रीय विषमता: भारतीय सन्दर्भ

डॉ॰ अजीत कुमार तिवारी

एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

www.shodh.net

Web Portal of Humanity & Social Science Research

महाराष्ट्र	5.6	6.9	9.5	3.2	4.7	7.1
पंजाब	5.4	4.4	5.4	3.5	2.5	3.5
हरियाणा	6.3	4.7	9.3	3.7	2.2	7.3
गुजरात	4.8	8.0	10.5	2.8	6.0	9.0
तमिलनाडु	5.0	6.4	7.9	3.5	5.3	6.8
केरल	2.6	5.9	8.6	1.1	4.8	7.9
कर्नाटक	5.3	7.1	7.6	3.2	5.4	6.4
आन्ध्र प्रदेश	5.3	5.3	8.0	3.0	3.8	6.9
औसत	**5.03**	**6.08**	**8.35**	**3.0**	**4.33**	**6.86**
प॰बंगाल	4.6	6.9	6.6	2.3	5.1	5.5
मध्यप्रदेश	3.6	5.6	4.5	1.2	3.4	3.4
राजस्थान	5.9	6.5	7.6	3.2	4.0	5.6
असम	3.3	2.2	5.1	1.1	0.3	3.6
उड़ीसा	4.8	4.0	9.3	2.9	2.4	8.1
उत्तर प्रदेश	4.8	3.6	5.6	2.4	1.3	3.6
बिहार	4.7	2.0	8.3	2.5	NS*	6.6
औसत	**4.52**	**4.68**	**6.71**	**2.22**	**2.75**	**5.2**
संपूर्ण भारत	**4.8**	**5.43**	**7.58**	**2.64**	**3.65**	**6.08**

स्रोत : आर॰बी॰आई॰ पब्लिकेशन (2012)[4] से प्राप्त आंकडों पर आधारित

NS* = Not Significant

तलिका 3 में तीन समय श्रेणियो (1980-81 से 1989-90, 1990-91 से 1999-2000 एवं 2000-01 से 2009-10) के लिए विकसित एवं कम विकसित राज्यों के बीच निवल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पादों की तुलना की गयी है। तालिका में दिये गये तथ्यों के विश्लेषण से एक बात स्पष्ट है कि आर्थिक सुधारों से पूर्व (1980-81 से 1989-90) की तुलना में आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक दशक में (1990-91 से 1999-2000 तक) में राज्यों के बीच आर्थिक विषमता बढ़ी है जबकि आर्थिक सुधारों के दूसरे दशक अर्थात (2000-01 से 2009-10 तक) राज्यों के बीच आर्थिक विषमता में कमी आयी है तथा कुछ कम विकसित राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान के आर्थिक प्रदर्शन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक दशक में विकसित राज्यों विशेषकर गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र को अधिक लाभ हुआ। इस दशक में कृषि आधारित राज्य जैसे पंजाब एवं हरियाणा का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं रहा। कम विकसित राज्यों में प॰बंगाल, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश का प्रदर्शन संतोषजनक रहा जबकि बिहार, उत्तरप्रदेश एवं असम की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही। बाद के दशक अर्थात 2000-01 से

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly

Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

www.shodh.net

Web Portal of Humanity & Social Science Research

2009-10 के बीच बिहार, उड़ीसा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा जो इन राज्यों के बेहतर शासन प्रणाली (Good Governance) का भी द्योतक है।

सेट्टी (2003)[5] द्वारा 16 राज्यों पर किये गये अध्ययन के अनुसार 80 के दशक में जो विचरण गुणांक (Coefficient of Variation) 18% था 90 के दशक में बढ़कर 27% हो गया वहीं प्रति व्यक्ति GSDP का विचरण गुणांक 25% स बढ़कर 43% हो गया। आर्थिक सुधारों के पश्चात राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का भाग 50% से अधिक हो गया। 90 के दशक में दस राज्यों में सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर 7% से अधिक दर्ज की गई थी जबकि 80 के दशक में केवल 5 राज्यों में ही सेवा क्षेत्र की संवृद्धि 7% से अधिक थी, जबकि पिछड़े राज्यों में कृषि क्षेत्र की संवृद्धि दर भी बहुत कम थी।[6]

माथुर (2005)[7] ने विभिन्न सूचकांकों के आधार पर अन्तर-राज्य विषमता का अध्ययन किया, इस अध्ययन के कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्न है।

1. आर्थिक सुधारों से पूर्व की तुलना में आर्थिक सुधारों के पश्चात प्रति व्यक्ति आय के विचरण गुणांक में वृद्धि हुई है।
2. कृषि क्षेत्र में विषमता में कमी आयी जबकि सेवा क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र का विचरण गुणांक 90 के दशक में बढ़ा।
3. विकसित राज्यों के बीच आय विषमता में कमी आयी जबकि पिछड़े राज्यों की आय विषमता आर्थिक सुधारों के पश्चात बढ़ी।

नायक एवं अन्य (2012)[8] द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार अस्सी के दशक का विचरण गुणांक (Coefficient of Variation) जो 27.4: था, नब्बे के दशक में बढ़कर 32.4% हो गया लेकिन यह विचरण गुणांक (CV) 2000 से 2010 के बीच घटकर 21.1% पर आ गया। प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद (Per Capita NSDP) के लिए भी यही प्रवृति दृष्टिगोचर होती है। विचरण गुणांक (CV) जो अस्सी के दशक में 48% थी, 90 के दशक में बढ़कर 53.5% हो गयी जबकि 2000 से 2010 के बीच यह घटकर 26.3% रह गयी। अर्थात ग्यारहवीं योजना के अन्तिम वर्षों में पिछड़े राज्यों ने भी बेहतर आर्थिक प्रदर्शन किया है।

क्षेत्रीय विषमता के कारण

भारत में क्षेत्रीय विषमता के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारण हो सकते हैं लेकिन इस शोध पत्र में भारत की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करेंगे जिसके कारण ये विषमताएँ बढ़ी है। जैसा कि UPA सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस तथ्य की ओर संकेत किये गये कि योजनागत आवंटन एवं केन्द्रीय सरकारों द्वारा प्रदत्त सहायता के विकृतियों के कारण ये क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी जिसने न केवल आर्थिक संवृद्धि एवं राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के अन्तराल को बढ़ाया बल्कि सामाजिक तनाव में भी वृद्धि की। जिसने आतंकवाद तथा नक्सलवाद जैसी समस्याआं की पृष्ठभूमि को इन पिछड़े राज्यों में तैयार होने का पर्याप्त मौका दे दिया।

निम्न तालिका में पहली योजना से आठवी योजना तक का प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय प्रदर्शित है। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि विकसित राज्यों का औसत पहली योजना से लेकर आठवीं योजना तक क्रमश: 58, 71, 16, 199, 337, 765, 1233 और 2673 थी जबकि पिछड़े राज्यों का औसत क्रमश: 37, 47, 89, 112, 217, 557, 840, 1757 था, अर्थात किसी भी योजना में पिछड़े राज्यों का प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय विकसित राज्यों से अधिक नहीं था। पहली योजना में जहाँ पंजाब का प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय 175 था वहीं बिहार एवं उत्तर प्रदेश का मात्र 25 था। पांचवीं योजना में पंजाब एवं हरियाणा का प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय क्रमश: 531 एवं 481 था, वहीं बिहार एवं उत्तर प्रदेश का मात्र 155 एवं 237 था। आठवीं योजना में यह अंतराल और बढ़ गया जहाँ महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा का प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय क्रमश: 3101, 2951 एवं 2838 था वहीं बिहार एवं उत्तर प्रदेश का मात्र 592 एवं 1372 ही था।

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly

Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

www.shodh.net

Web Portal of Humanity & Social Science Research

तालिका - 4

प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय

राज्य	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना	पांचवी योजना	छठी योजना	सातवीं योजना	आठवीं योजना
महाराष्ट्र	37	57	103	199	372	98.3	1434	3101
पंजाब	175	146	212	316	531	1175	1695	2951
हरियाणा	--	--	--	358	481	1385	1871	2838
गुजरात	58	76	108	204	376	1037	1485	2700
तमिलनाडु	28	57	98	134	201	651	1063	2427
केरल	31	49	101	156	224	578	727	2378
कर्नाटक	46	62	100	128	276	614	749	3138
आन्ध्र प्रदेश	33	52	91	98	236	584	841	1858
औसत	58	71	116	199	337	765	1233	1673
प॰बंगाल	54	48	80	82	200	600	653	1144
मध्य प्रदेश	34	48	84	114	254	687	1146	1742
राजस्थान	39	53	97	120	237	577	718	2548
असम	29	57	103	136	190	526	850	2066
उड़ीसा	56	54	120	113	207	536	897	2123
उत्तर प्रदेश	25	32	72	132	237	535	803	1372
बिहार	25	40	67	85	155	456	626	592
औसत	37	47	89	112	217	557	840	1757

स्रोत: सी.एम.आई.ई. बेसिक स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू इंडियन इकोनोमी एवं नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

निम्न तालिका राज्यों के बीच निवेश वितरण की स्थिति को दिखाता है।

शोध संचयन SHODH SANCHAYAN

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly
Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

www.shodh.net
Web Portal of Humanity & Social Science Research

तालिका - 5

राज्यों में प्रति व्यक्ति पूंजी प्रवाह की स्थिति 1999/2000/2001

राज्य	प्रति व्यक्ति सार्वजनिक एवं निजी निवेश	पति व्यक्ति योजनागत व्यय	प्रति व्यक्ति संस्थागत निवेश	प्रति व्यक्ति कुल साख उपयोगिता
महाराष्ट्र	17556	1120	660	14890
पंजाब	12688	1244	1078	7707
हरियाणा	9201	861	827	5098
गुजरात	33875	1285	720	5827
तमिलनाडु	26292	837	709	9194
केरल	12235	810	1173	5872
कर्नाटक	24775	1499	688	6420
आन्ध्र प्रदेश	21447	1032	910	4668
औसत	**19758**	**1074**	**846**	**7460**
प॰बंगाल	7113	710	662	3674
मध्य प्रदेश	7287	652	725	2528
राजस्थान	6763	822	914	2419
असम	NA	NA	NA	NA
उड़ीसा	25525	627	1049	1706
उत्तर प्रदेश	3304	293	619	1638
बिहार	2852	319	546	669
औसत	**8807**	**570**	**753**	**2105**

स्रोत : भारत सरकार (2003)

साभार : एस.महेन्द्र देव, इन्क्लूसिव ग्रोथ इन इन्डिया (2008) पृष्ठ : ३१२

उपरोक्त तालिका विभिन्न प्रदेशों में निवेश वितरण की स्थिति को स्पष्ट करता है। सभी सूचकांकों में विकसित प्रदेशां की स्थिति पिछड़े प्रदेशों से बेहतर है। एक ओर जहाँ प्रति व्यक्ति सार्वजनिक एवं निजी निवेश की दृष्टिकोण से विकसित प्रदेशों का औसत 19758 है वहीं पिछड़े प्रदेशों का औसत मात्र 8807 है। 33875 के साथ गुजरात पहले स्थान पर है, वहीं मात्र 2852 के साथ बिहार सबसे नीचे है। प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय में विकसित प्रदेशों का औसत 1074 है वहीं पिछड़े प्रदेशों का औसत 570 है। कर्नाटक एवं गुजरात की प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय क्रमश: 1499 एवं 1285 है वहीं उत्तर प्रदेश एवं बिहार का प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly
Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

www.shodh.net
Web Portal of Humanity & Social Science Research

मात्र 293 एवं 319 है। जहाँ तक प्रति व्यक्ति संस्थागत निवेश का प्रश्न है, यहाँ भी विकसित प्रदेशों ने ही निवेश के एक बड़े भाग को आकर्षित किया है। केरल एवं पंजाब इस सदर्भ में अग्रणी प्रदेश हैं वहीं बिहार एवं उत्तर प्रदेश पिछले पायदान पर कायम हैं। प्रति व्यक्ति कुल साख उपयोगिता में भी विकसित एवं पिछड़े प्रदेशों के औसत में तीन गुने से अधिक का अंतर है। एक ओर जहाँ महाराष्ट्र का प्रति व्यक्ति साख उपयोगिता 14890 है वहीं बिहार में यह मात्र 669 है।

तालिका - 6

प्रति व्यक्ति पूंजी प्रवाह में अग्रणी राज्य

प्रति व्यक्ति प्रवाह	पांच बड़े राज्य
योजनागत व्यय	गोवा, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र
सार्वजनिक एवं निजी निवेश	गोवा, गुजरात, तमिलनाड, उड़ीसा, कर्नाटक
संस्थागत निवेश	गोवा, केरल, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान
साख उपयोगिता	महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक

प्रति व्यक्ति पूंजी प्रवाह में अग्रणी राज्य

स्रोत : भारत सरकार (2003)

साभार : एस.महेन्द्र देव, इन्क्लूसिव ग्रोथ इन इन्डिया (2008) पृष्ठ : 353

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति पूँजी प्रवाह सर्वाधिक विकसित राज्यों की ओर रहा है। यहाँ उड़ीसा एक अपवाद है, जहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में काफी मात्रा में निवेश हुआ है।

निम्न तालिका यह स्पष्ट करती है कि पिछड़े राज्यो को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में उत्तरोत्तर सापेक्षिक रूप मे कमी आती जा रही है।

तालिका - 7

पिछड़े राज्यों' को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता (प्रतिशत में)

योजनायें	केन्द्रोय सहायता (प्रतिशत में)
छठी योजना (1980-85)	46
सातवीं योजना (1985-90)	42
आठवीं योजना (1992-97)	37
नौवीं योजना (1997-2002)	38
दसवीं योजना (2002-2007) (अनुमानित)	36

'यहाँ असम, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार एवं राजस्थान को पिछड राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।

स्रोत : दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002.07), तालिका 6.1 पृष्ठ-118 से संकलित

उपरोक्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि आधारभूत संरचनाओं एवं आय तथा पूंजी के प्रवाह में सीधा सम्बन्ध है अर्थात जिस प्रदेश एवं क्षेत्र की आधारभूत संरचना बेहतर है वहाँ सापेक्षिक रूप से अधिक निवेश हुआ जबकि खराब आधारभूत संरचना वाले प्रदेशों एवं क्षेत्रों की स्थिति बिगड़ती चली गयी। पूर्वी उत्तर प्रदेश

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly
Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

www.shodh.net
Web Portal of Humanity & Social Science Research

एवं बिहार इसके स्पष्ट उदाहरण है। प्रश्न यह उठता है कि यदि इन पिछड़े क्षेत्रों एवं प्रदेशों में निवेश को यही स्थिति रही तो हम समावेशी विकास के उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर सकेंगे।

निजी निवेश का प्रवाह स्वाभाविक रूप से विकसित क्षेत्र की तरफ ही होगा। लेकिन यहाँ केन्द्र सरकार की नीतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि क्या सार्वजनिक वित्तीय आवण्टन एवं सार्वजनिक निवेश का प्रवाह भी सापेक्षिक रूप से विकसित प्रदेशों एवं क्षेत्रों की ओर ही होना चाहिए, जबकि हाल के वर्षों में कम विकसित राज्यों जैसे बिहार एवं उड़ीसा ने अपने बेहतर प्रदर्शन से यह सिद्ध कर दिया कि यदि इन राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो ये भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सकते हैं।

सुझाव एवं उपसंहार -

उपरोक्त विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि प्रति व्यक्ति पूंजी के प्रवाह में असन्तुलन क्षेत्रीय असन्तुलन का एक मुख्य कारक है।

संघीय व्यवस्था में सबसे प्रमुख समस्या केन्द्र तथा राज्यों के बीच संसाधनों के स्रोत बंटवारे से उत्पन्न असन्तुलन को न्यूनतम करने से सम्बन्धित है। अत: योजना आयोग एवं वित्त आयोग का संसाधनों के बंटवारे के नीतिगत आधार में एक संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि पिछड़े राज्यों एवं क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या एवं गरीबी के आधार पर पर्याप्त पूंजो आवंटन मिल सके। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि केवल पूंजी आवंटन को बढ़ा देने मात्र से पिछड़े क्षेत्रों एवं राज्यों का विकास हो जाएगा, यह आवश्यक नहीं हैं। यहाँ आवश्यकता है बेहतर शासन व्यवस्था की जो योजनाओं को पूरी इमानदारी से लागू करे। यहाँ बिहार में आये राजनैतिक परिवर्तन को उद्धृत किया जा सकता है जहां 2005 तक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर मात्र 3.5% थी जो बढ़कर लगभग 11% पहुँच गयी। राज्य का राजस्व 2004-05 में जहाँ 15714 करोड़ था वहीं 2009-10 में 37870 करोड़ हो गया। राज्य का विकास व्यय 40% से बढ़कर 67% पहुँच गया। पूंजीगत व्यय में इस दौरान तीन गुने से अधिक की बढ़ोतरी हुयी।[9] अर्थात कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य एवं अधाररभूत संरचनाओं में बड़े निवेश के साथ सख्त एवं ईमानदार शासन व्यवस्था (Good Governance) ही क्षेत्रीय विषमता को कम करके समावेशी विकास के उद्देश्यों को पूरा कर सकता है।

संदर्भ:-

1. शंकर आचार्य (2006), 'इकोनोमिक ग्रोथ : सम रिफलेक्शन्स', इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 41, नं. 44, 4 नवम्बर
2. मोन्टेक सिंह अहलूवालिया (2000), 'इकोनोमिक परफॉरमेन्स ऑफ स्टेट्स इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड', इकानोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, 6 मई
3. मोहन्ती, दीपक (2012) (मक) 'रीजनल इकोनोमी ऑफ इण्डिया', आर॰बी॰आई॰ एवं एकेडमिक फाउण्डेशन, पृष्ठ-47
4. मोहन्ती, दीपक (2012) (मक) पृष्ठ-44-46
5. सेट्टी, एस.एल. (2003)ए ग्रोथ ऑफ एसडीपी एण्ड स्ट्रक्चरल चेन्ज इन स्टेट इकोनोमिज : इंटर स्टेट कॉम्पेरिजन, ई. पी.डब्ल्यू., 6 दिसम्बर
6. विस्तृत विश्लेषण हेतु देखें देव एवं रवि (2003)
7. माथुर, ए. (2005)ए स्पेसियल इन्कम इनइक्वैलिटी एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेन्ट, पेपर प्रेजेन्टेड एट द नेशनल सेमिनार ऑन एक्सीलरेट इकोनोमिक ग्रोथ एण्ड रिजनल बैलेंस ऑरगेनाइज्ड बाइ आई.ई.ए., आई.एस.आई.डी. एण्ड आई.एच.डी., नई दिल्ली, 16-18 सितम्बर
8. नायक पी॰के, एस॰के॰चटोपाध्याय, अरूण, विष्णु एवं वी॰धन्या (2012), इन्क्लूसिव ग्रोथ एण्ड रिजनल डाइमेन्सन, मोहन्ती दीपक (मक)ए 'रीजनल इकोनोमी ऑफ इण्डिया', आर॰बी॰आई॰ एवं एकेडमिक फाउण्डेशन
9. इकोनोमिक टाइम्स, मई 29, 2011, पृष्ठ-4

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly

Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

समावेशी विकास एवं क्षेत्रीय विषमता: भारतीय सन्दर्भ

डॉ॰ अजीत कुमार तिवारी

एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

www.shodh.net

Web Portal of Humanity & Social Science Research

संलग्नक 1

आर्थिक सूचकांक	1950-51	1970-71	1990-91	2000-01	2007-08	वृद्धि
१. साधन, लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (नियत कीमत पर)	224786	474131	1083572	1864300	3898958	17 गुना
२. प्रति व्यक्ति आय (नियत कीमत पर)	5708	8091	11535	16172	30354	5 गुना
३. औद्योगिक उत्पाद का सूचकांक (1993-94 की कीमत के आधार पर)	7.9	28.1	91.6	162.6	277.1	35 गुना
४. कृषि उत्पादन का सूचकांक (1981-82 के त्रैवार्षिक समाप्ति के आधार पर)	46.2	85.9	148.4	165.7	207.1	4.48 गुना
५. सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में चालू बाजार कीमत पर)	8.4	15.1	26.0	24.3	38.1	4.5 गुना
६. सकल घरेलू बचत (जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में चालू बाजार कीमत पर)	8.6	14.2	22.8	23.7	36.9	4.2 गुना
७. खाद्यान्न उत्पादन (मिट्रिक टन)	50.8	108.4	176.4	196.8	230.8	4.5 गुना
८. विद्युत उत्पादन (उपयोगिता) (बिलियन किलोवाट घण्टा)	5	56	264	466	704	141 गुना
९. विदशी विनिमय कोष (यू.एस.डॉलर, मिलियन)	1914	584	2236	39554	299230	156 गुना
१०. जीवन प्रत्याशा	32.1	45.6	58.7	62.5	63.5 (2006-07)	2 गुना
११. साक्षरता दर	18.3	34.4	52.2	64.8		3.5 गुना
स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11						

शोध संचयन SHODH SANCHAYAN

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research

मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly

Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

www.shodh.net

Web Portal of Humanity & Social Science Research

संलग्नक 2

विकसित राज्य	निवल प्रति व्यक्ति आय (2008-09) (वर्तमान कीमत पर)	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का : (2004-05)	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन कि.ग्रा. (2004-05)	प्रति व्यक्ति सकल औद्योगिक उत्पादन	कुल जनसंख्या में कुल कामगारों का : (2001)	नगरीय जनसंख्या का अनुपात (%) (2001)	प्रति व्यक्ति घरेलू बिजली उपभोग (2006-07) in KWH	प्रति व्यक्ति साख जमा अनुपात (2008)	समाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना का अनुपात (1999)
1. महाराष्ट्र	54867	38.1	100.6	34,990	35.9	42.4	135.9	94.7	112.8
2. पंजाब	52879	20.9	985.1	20,783	32.2	34.0	216.5	66.3	187.6
3. हरियाणा	68914	24.1	562.3	33,634	29.6	28.9	134.8	60.6	137.5
4. गुजरात	49251	31.8	95.6	48,468	33.7	37.4	119.4	65.2	124.3
5. तमिलनाडु	45058	28.9	94.8	24,773	38.1	44.0	187.6	115.4	149.1
6. केरल	49316	19.7	20.2	10,921	25.9	26.0	155.1	65.3	178.7
7. कर्नाटक	41513	33.4	186.6	19,715	36.7	34.0	103.2	78.0	104.9
8. आन्ध्र प्रदेश	40902	29.9	166.0	12,945	38.1	37.3	122.8	69.6	103.3
औसत	50337.50	28.35	276.4	25778.62	33.77	34.63	146.91	76.81	137.27
पिछड़े राज्य									
9. प॰बंगाल	36322	34.3	188.4	8598	28.8	28.0	75.5	61.4	111.3
10.मध्य प्रदेश	21648	48.6	212.5	7227	31.7	26.5	59.0	60.3	76.8
11. राजस्थान	27001	34.4	195.1	7382	30.9	23.4	59.0	82.0	75.9
12.असम	23993	34.4	126.2	7783	36.6	12.9	35.7	41.2	77.7

शोध संचयन SHODH SANCHAYAN

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally Indexed Refereed Research Journal & A complete Periodical dedicated to Humanities & Social Science Research
मानविकी एवं समाज विज्ञान के मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध पर केन्द्रित

Half Yearly

Vol-4, Issue-1
15 Jan-2013

समावेशी विकास एवं क्षेत्रीय विषमता: भारतीय सन्दर्भ

डॉ॰ अजीत कुमार तिवारी

एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

www.shodh.net

Web Portal of Humanity & Social Science Research

13. उड़ीसा	29464	57.2	177.2	6065	26.1	15.0	70.8	56.6	81.0
14.उत्तर प्रदेश	18710	40.9	206.4	6103	23.7	20.8	73.0	44.9	101.2
15.बिहार	13663	54.4	262.9	1378	25.4	10.5	13.9	29.7	91.3
औसत	24400.14	37.17	195.52	6362.28	27.6	19.58	55.27	53.72	75.61
	40141*	37.2	178.7	15337	30.4	27.8	98.8	74.2	100

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11ए स्टैटिस्टिकल आउटलाईन आफं इन्डिया 2009-11, टाटा सर्विसेज लिमिटेड, 2009-10

देश का औसत 2004-05 के आधार पर

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN